रिधि दर्पण

Web. : ridhidarpan.com

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष 08 अंक 47 27 फरवरी - 05 मार्च, 2023 पृष्ठ : 8 दिल्ली मूल्य 2 रूपये R.N.I.No.-DELHIN/2015/61255

3 भाजपा में शामिल हुए पार्षद पवन सहरावत

7 अर्थव्यवस्था की विकास दर ऊंची रहेगी: राजीव

8 टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम रूबीना दिलैक

देश कह रहा है, भाजपा का खिलेगा कमल : मोदी

हरि सिंह रावत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलांग में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने एक नया नारा भी दिया- मेघालय मांगे, भाजपा सरकार।

पीएम मोदी ने कहा, "जब मैं मेघालय के बारे में सोचता हूं तो मैं प्रतिभाशाली लोगों, जीवंत परंपराओं के बारे में सोचता हूं, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी सोचता हूं। मेघालय का संगीत जीवंत है। फुटबॉल के लिए जुनून है। मेघालय के हर कोने में रचनात्मकता है।"

प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं... वो आजकल माला जपते हैं और कह रहे हैं कि- मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, देश का कोना कोना कह रहा है- मोदी तेरा कमल खिलेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेघालय इसमें अपना मजबूत योगदान दे रहा है। हम इसे और आगे

बढ़ाना चाहते हैं और राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मेघालय और पूर्वोत्तर की जनता कमल और भाजपा के साथ है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, मेघालय को 'परिवार पहले' की जगह 'लोग पहले' की सरकार की जरूरत है। मेघालय को वंशवादी राजनीति से मुक्त होना चाहिए। दिल्ली ही नहीं, मेघालय में भी पारिवारिक पार्टियों ने अपनी तिजोरी भरने के लिए मेघालय को एटीएम में तब्दील कर दिया है।"

पीएम मोदी ने कहा, "मेघालय के हितों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई... आपको छोटे-छोटे मुद्दों पर बांटा गया। इस राजनीति ने आपका बहुत नुकसान किया है... यहां के युवाओं का बहुत नुकसान किया है। मेघालय आज Family First की बजाए People First वाली सरकार चाहता है। इसलिए आज 'कमल का फूल' मेघालय की मजबूती, शांति और स्थिरता का पर्याय बन गया है।" इससे पहले प्रधानमंत्री ने शिलांग में एक रोड शो भी किया। इस दौरान लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। बाद में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "इस रोड शो की तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। मेघालय में चारों तरफ भाजपा ही भाजपा दिख रही है। पर्वतीय हो या मैदानी इलाका... गांव हो या शहर हर तरफ कमल खिलता दिख रहा है।"

दिल्ली में पिछले एक साल में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब : केजरीवाल

इन्दू रावत

नई दिल्ली। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पिछले एक साल में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कहा कि ये जानकर अच्छा लगा कि एलजी साहेब ने आखिरकार कानून व्यवस्था पर मंगलवार को बैठक ली। उन्होंने कहा कि एलजी साहेब को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी बैठक जल्दी जल्दी करनी चाहिए। इसके साथ ही केजरीवाल ने

एलजी की खबर को ट्विटर पर शेयर किया है।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को डीसीपी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार, पुलिस की सख्ती और जांच में खामियों जैसे कई मुद्दे उठाए थे। उन्होंने पुलिस से अपील की थी कि आगामी जी-20 सम्मेलन के मद्देनजर हर स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से कदम उठाये जाएं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने

शेष पृष्ठ 6 पर

आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं: राष्ट्रपति

चन्द्र मोहन सिंह

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) का 99वां दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके साथ ही यह पहला मौका होगा जब छात्र गाउन की जगह परंपरागत भारतीय परिधान धारण कर अपनी-अपनी डिग्रियां प्राप्त कीं।

डीयू के दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। यह बहुत खुशी का विषय है कि इस बार डीयू से डिग्री, मेडल और पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वालों में छात्राओं की संख्या अधिक है। मैं अपने गांव से शहर जाकर पढ़ने वाली पहली लड़की थी, लेकिन अब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।

यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के खेल परिसर स्थित बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित किया गया है। इस समारोह के दौरान कुल 170 विद्यार्थियों को मैडल व पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें 51 पुरुष और 119 महिला विद्यार्थी शामिल थीं।

वहीं, चिकित्सा क्षेत्र में डीएम व एमसीएच के 47 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान गई हैं। साथ ही

शेष पृष्ठ 6 पर

देश नफरत की आग भड़काई जा रही है : सोनिया गांधी

डी एस नेगी

दिल्ली । सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा नफरत की आग भड़का रही है तथा अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और विपक्ष की आवाज दबाने के साथ नफरत की आग भड़काई जा रही है।

वह यहां पार्टी के 85वें महाधिवेशन में बोल रही थीं। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा नफरत की आग भड़का रही है तथा अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है।

सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 'भाजपा-आरएसएस' की सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है तथा विपक्ष की आवाज

शेष पृष्ठ 6 पर

प्रजातंत्र को तोड़ने की साज़िश रच रही सरकार : खरगे

पूर्ति अग्नि होत्री

उन्होंने पार्टी के 85वें महाधिवेशन में दिए अपने अध्यक्षीय भाषण में मोदी सरकार पर 'नफरत का माहौल', महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को लेकर तीखा प्रहार किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर देश को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी है।

उन्होंने पार्टी के 85वें महाधिवेशन में दिए अपने अध्यक्षीय भाषण में मोदी सरकार पर 'नफरत का

माहौल', महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को लेकर

शेष पृष्ठ 6 पर

भारत में 47 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता : पीयूष गोयल

तीरथ राज

नई दिल्ली। भारत के लिए 2047 तक 47 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना बिलकुल भी अकल्पनीय नहीं है। पिछले आठ-नौ सालों में देश ने बेहतर गवेर्नेंस को देखा है। इसके साथ ही हमारे देश में एक विशाल प्रतिभा पूल है। देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में ये बातें काफी सहायक होंगी। ये बातें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन

द्वारा आयोजित 17वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन (आईडीएस 2023) के दौरान कहीं।

उन्होंने इस मौके पर कहा कि राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, 1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5 गुना वृद्धि देखी है, हम $300 बिलियन से $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गए हैं।

शेष पृष्ठ 6 पर

रिधि दर्पण
27 फरवरी-05 मार्च 2022, नई दिल्ली

सम्पादकीय -

भारतीय समाज

हरिसिंह रावत
सम्पादक

हमारे ही देश में एक वह भी समय था जब पढाऩे वाले और पढ़ने वालों के बीच गुरू शिष्य का पवित्रा रिश्ता होता था। गुरू का स्थान माता पिता से भी ऊंचा माना जाता है। बहुत पुरानी बात को जाने भी दें तो स्वाधीनता प्राप्ति से पहले तक स्थिति नितांत भिन्न थी। आज भी पुराने लोग अपने समय के स्कूल कॉलिज के दिनों को याद करके इस बात की पुष्टि करने में नहीं हिचकिचाएंगे।

हमारे यहां 1947 के बाद से ही शिक्षा की नीति पर विचार विमर्श चलता चला आ रहा है। भांति भांति के प्रयोग होते आए हैं, हो रहे हैं। पुरानी शैली को दरकिनार कर दिया गया है। नई पुख्ता कोई बन नहीं पायी। हालत यह है कि न इधर के रहे, न उधर के। प्रदेश अपनी मनमर्जी से, जब जैसी सरकार होती है, परिवर्तन कर डालते हैं, बेशक अच्छी भावना से, अच्छे के लिए किंतु कुछ भी अच्छा सामने दिखाई नहीं पड़ता। कभी कहीं अंग्रेजी हटा दी जाती है कभी पुनः लागू कर दी जाती हैं। कहीं त्रि- भाषायी फामूर्ला जारी हो जाता है। फिर अचानक वह समाप्त कर दिया जाता है। बेचारे बच्चे विषयों की भरमार तथा बस्ते के नित बढ़ते भार से हलकान परेशान रहते हैं।

आज टयूशन के बिना पढ़ाई संभव ही नहीं रही। वह भी हर विषय के लिए अलग अलग टयूटर, अलग अलग दिशा में अलग अलग दूरी पर। बेचारा बच्चा चक्करघिन्नी बना रहता हैं। हमने अपने बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया है। उन्हें खेलने कूदने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अपनी करनी का दोष हम बच्चों के सिर मढ़ने से जरा भी नहीं हिचकते। उन्हें उच्छृंखल की संज्ञा दे देते हैं। स्कूल टीचर्स से पढ़ाने के अतिरिक्त हर संभव काम लेना आम बात है। हमारे कर्णधारों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। शारीरिक दंड देना अपराध बना दिया गया है। बेचारे शिक्षक शिक्षिकाएं समझ नहीं पाते कि उद्दंड छात्रों को वे संभालें तो कैसे? स्थिति विस्फोटक हो चली है मगर हमारे शिक्षाशास्त्री खरगोश की नींद सो रहे हैं। स्कूलों कालेजों में शिक्षक पढ़ाने से इतर पालिटिक्स में अधिक व्यस्त नजर आते हैं। उन्हें कक्षा में पढ़ाने से कहीं अधिक टयूशन पढ़ाने में रूचि रहती है। किसी ने खूब कहा कि आज पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के बीच मात्रा इतना रिश्ता है कि छात्रा फीस देता है और शिक्षक पगार लेता है। एक समय था कि डाक्टर हकीम वैद्य का स्थान हमारे मन में भगवान के बाद रहता था। डाक्टर को अपनी परेशानी बताने भर से आधी बीमारी जैसे दूर हो जाती थीं। तब डाक्टर पर विश्वास होता था। आज डाक्टरी एक पुण्य का काम नहीं मात्रा धंधा बन चुका हे। पैसा कमाना भर ही एक मात्रा उद्देश्य रह गया है। आंखों देखी बता रहा हूं- डाक्टर साहिब आला एक को लगा रहे हैं, नब्ज दूसरे की पकड़े हैं, हकीकत तीसरे की सुन रहे हैं, नुस्खा चैथे का लिख रहे हैं। मन में आया कि है भगवान तू ने इन्हें चार हाथ क्यों न दिये। हर डाक्टर के यहां भीड़ ही भीड़। कई डाक्टर 4-4, 5-5 दिन बाद का एपायंटमेंट देते हैं। बताइए मरीज इस बीच करें तो क्या करें। डाक्टर बढ़ते जा रहे हैं। भीड़ उनकी तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती जा रही हैं इनकी फीस। बस खुदा की पनाह। हर बार जाने पर बढ़ी हुई मिलती है। भांति भांति के टेस्ट लिखना सामान्य बात है। याद आती है पुराने दिनों की जब डाक्टर साहिब अपने अनुभव से रोग का निदान कर लेते थे। तब जगह जगह पैथालजिकल लैब कहां नजर आते थे। टेस्टों के बारे में अनेक बातें कही सुनी जाती हैं कि इन में लिखने वाले डाक्टर का परसनटेज बंधा होता है। नई नई महंगी से महंगी दवाइयां लिखना तो आम बात है। ढेरों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तथा उनका पूरा का पूरा ढांचा इसी पर तो टिका रहता है। कहा जाता है कि डाक्टरों को फारेन टूर तक कीमती तोहफे दे दे कर हर कंपनी अपनी नई दवाइयां लिखने को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। वैसे भी डाक्टरी पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। फीसें ही लाखों में होती हैं। कई कई साल की पढ़ाई का खर्च। फिर आज मात्रा एम.बी.बी.एस कर लेने से तो काम नहीं चलता। पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन जरूरी ही है। फिर बंगला, कार, तामझाम भी आवश्यक होते हैं।

कलम से

शिन्दे अब शिवसेना प्रमुख

अशोक त्रिपाठी

महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। लगभग 60 साल पहले बालासाहेब ठाकरे ने जिस शिवसेना का गठन किया था, उसके दावेदार पहले उनके भतीजे राज ठाकरे माने जा रहे थे लेकिन बालासाहेब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव को अपने जीते जी युवराज घोषित कर दिया था। राजठाकरे की नाराजगी का यही प्रमुख कारण था और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मन से) के नाम से नयी पार्टी बना ली थी। इसीलिए 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ गये और भाजपा इस समझौते के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि लम्बी खींचतान के बाद शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की मदद से सरकार बनायी। शिव सेना इन दोनों पार्टियों के विरोध में ही चुनाव लड़ती आयी थी, इस लिए बाला साहब ठाकरे के कभी निकटस्थ रहे एकनाथ शिंदे ने इसी कमजोर नस को पकड़ कर शिव सेना के कई विधायकों को तोड़ लिया और भाजपा के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे से सत्ता छीन ली। सत्ता छीनने के बाद एक नाथ शिंदे ने शिव सेना पर ही अपना अधिकार जताया। मामला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक पहुंचा और चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिव सेना मानकर पार्टी का चुनाव चिह्न तीर और धनुष उसे दे दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनाव चिह्न मशाल मिला है। इस प्रकार एक नाथ शिंदे अब शिव सेना प्रमुख बन गये हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि हम कैसे घड़ी की सुइयां पीछे कर सकते हैं क्योंकि विचार तो उस विश्वास मत पर भी करना होगा जो कभी हुआ ही नहीं। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर, उद्धव ठाकरे गुट को मिले चुनाव चिह्न पर भी बिहार में समता पार्टी ने अपना अधिकार जताया है।

शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की सुनवाई के दौरान पांच जजों के संविधान पीठ ने फिर से उद्धव ठाकरे गुट पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब हम मामले में क्या राहत दे सकते है ? हम कैसे घड़ी की सुईयों को पीछे कर सकते हैं। ऐसे मामले में अदालत कैसे दखल दे? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या आप इस धारणा पर आगे बढ़ रहे हैं कि घटनाओं से आगे निकलने के बावजूद हम घड़ी को वापस सेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि हमें उस विश्वास मत को भी अमान्य करना है जो कभी हुआ ही नहीं। हम आपस में इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि इस चरण में किस तरह की राहत पर विचार किया जाए। क्या अदालत को उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए? इसके बहुत गंभीर परिणाम हैं।

उधर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना प्रमुख नामित किया गया। कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट के साथ विवाद में शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे पार्टी का चुनाव चिह्न तीर-धनुष आवंटित किया था। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक अनुशासन समिति बनाने का प्रस्ताव पेश किया। सामंत ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके प्रति निष्ठावान 16 विधायकों का नाम लिए बिना कहा, अनुशासन समिति पार्टी के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगी और पार्टी के खिलाफ काम करने वाले पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आदेश पर रोक नहीं लगा सकते, यह पार्टी के भीतर एक अनुबंधात्मक संबंध है। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। उनसे दो हफ्ते में जवाब मांगा गया है। बैंक खाते और प्रापर्टी टेकओवर करने पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के आदेश की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर तीन जजों की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।

एकनाथ शिंदे गुट ने याचिका पर सवाल उठाया. नीरज किशन कौल ने कहा कि ये मामला हाईकोर्ट जाने का है, ये लोग पहले भी दो बार हाईकोर्ट गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है लेकिन हाईकोर्ट के पास ही जाना चाहिए। कौल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने को हरी झंडी दी थी. चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई थी।

उद्धव ठाकरे की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग के फैसले का आधार बहुमत है। जबकि 38 विधायकों के आधार पर फैसला दिया गया लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का आधार विधायक दल में बहुमत है। ईसी ने यह कहकर गलती की कि विभाजन हुआ है।

चुनाव आयोग ने उन विधायकों की संख्या पर भरोसा करके गलती की है, जो अयोग्यता के दायरे में हैं। ईसी को संविधान पीठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था. शिंदे खेमे के विधायकों के अयोग्य होने की संभावना है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने शिंदे गुट से पूछा, ये एक मुद्दा है, उन्होंने विधायक दल के बहुमत को आधार बनाया है. सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि शिवसेना का संविधान ऑन रिकॉर्ड नहीं था, जबकि उसके प्रमाण हैं. विधायिका की टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी को आधार बनाया गया।

राज्यपाल का तथ्यपरक उल्लेख

डॉ दिलीप अग्निहोत्री-

बजट सत्र में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियों का तथ्य के साथ उल्लेख किया है। ग्लोबल समिट और जी 20 सम्बन्धी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लिए अभूत पूर्व अवसर थे। इस अवधि में तैतीस लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। जी 20 देशों तक उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा हुई। इसके साथ ही साँस्कृतिक स्थलों के विश्व स्तरीय विकास की तरफ भी दुनिया का ध्यान आकृष्ट हुआ। यह संयोग था कि इसके बाद प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र प्रारम्भ हुआ। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल के अभिभाषण में भी उत्तर प्रदेश के विकास को रेखांकित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को फाइव ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उनकी प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के योगदन की घोषणा की थी। योगी का कहना था कि देश की फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश का योगदान वन ट्रिलियन होगा। इसी के साथ योगी ने केंद्र की योजनाओं में उत्तर प्रदेश को बढ़त दिलाई। उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सक्रिय है। विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश के प्रति उद्योग जगत की मान्यता बदली है। इसके पहले यहां निवेश में उनका कोई उत्साह नहीं रहता था। निवेश के लिए आवश्यक सभी तत्वों का यहां अभाव था। इसमें पहला तत्व कानून व्यवस्था का होता है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले इस ओर ही ध्यान दिया था। कहना था कि बेहतर व्यवस्था में ही विकास कार्यों का क्रियान्वयन सम्भव होता है। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती, उधर उद्योगपति निवेश का जोखिम नहीं उठाना चाहते। पहले उत्तर प्रदेश की यही दशा थी। इसके बाद व्यापार सुगमता की आवश्यकता होती है। योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में इसका रिकार्ड भी शानदार हो गया। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से निकल कर विकसित हो रहा है। यहां केवल निवेश प्रस्ताव नहीं आ रहे है, बल्कि हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जमीन पर भी उतर रहे है।

उत्तर प्रदेश में ढांचागत व अन्य निर्माण के रिकार्ड कायम हुए हैं। इसमें एक्सप्रेस वे और कनेक्टिविटी भी शामिल है। औद्योगिक विकास के लिए इन सुविधाओं का विस्तार अपरिहार्य होता है। इसके साथ ही बिजली की उपलब्धता, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सिंगल विंडो की पारदर्शी व्यवस्था, भूमि बैंक की स्थापना आदि भी आवश्यक होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेस वे को औद्योगिक विकास और प्रगति से जोड़ दिया है। उन्होंने एक्सप्रेस वे निर्माण मात्र को ही पर्याप्त नहीं माना। इनकी वास्तविक उपयोगिता औद्योगिक विकास से ही हो सकती है।उत्तर प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल कायम हुआ है। नेशनल से लेकर ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट का सिलसिला शुरू हुआ। उद्योगपतियों की उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। यह अनुकूल माहौल के कारण संभव हुआ है। यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर्स समिट माह फरवरी, 2018 में आयोजित किया था। इसमें प्राप्त निवेश के प्रस्तावों को तीन ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के साथ जमीन पर उतारते हुए लगभग चार लाख करोड़ रुपये से

अधिक का निवेश हो चुका है, अधिकांश इकाइयों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी स्थान पर है।

गरीबों के लिए आवास बनाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को कुल ऋण वितरण में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में निर्गत जीएसटी पंजीयन की कुल संख्या देश में सर्वाधिक है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला।

सुप्रीम कोर्ट में पीरियड लीव की याचिका खारिज़

रिधि दर्पण संवाददाता

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में पेड पीरियड लीव मामले में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस मसले पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि ये एक नीतिगत मुद्दा है, जो अदालत की सीमा के दायरे में नहीं आता। इसलिए बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करें। यहां सीजेआई ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह का न्यायिक आदेश महिलाओं के हितों के विरुद्ध भी साबित हो सकता है यानी ऐसी संभावना है कि छुट्टी की बाध्यता होने पर लोग महिलाओं को नौकरी देने से परहेज करें। अदालत का ये फैसला उन सभी महिलाओं के लिए एक झटका है, जो कोर्ट की ओर कुछ बदलाव की टकटकी लगाए बैठी थीं।

इस साल 11 जनवरी को वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेड पीरियड लीव को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि 1961 के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में महिलाओं को प्रेगनेंसी के वक्त तो वैतनिक अवकाश मिलता है, लेकिन पीरियड्स को लेकर इस तरह का कोई नियम नहीं है। कुछ कंपनियां स्वैच्छिक रूप से एक या दो दिन की छुट्टी देती हैं, तो वहीं देश के कुछ राज्यों में भी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को दो दिन की पेड लीव मिलती है। लेकिन इसे लेकर कोई एक देशव्यापी नियम नहीं है, जो सभी राज्यों और कंपनियों पर समान रूप से लागू होता हो। ऐसे में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वह मेंस्ट्रुअल पेन लीव दिए जाने को लेकर नियम बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे।

मेंस्ट्रुअल लीव को यदि आसान भाषा में समझे तो ये पीरियड्स के दौरान छुट्टी की बात है। क्योंकि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को मानसिक और शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इस समय उन्हें पेट दर्द, बदन दर्द,

उल्टी, तेज बुखार जैसी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, इसका काम के संबंध में प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। इसलिए देश-विदेश में पीरियड लीव की मांग समय-समय पर उठती रही है।

2016 में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रजनन स्वास्थ्य के प्रोफेसर जॉन गिलेबॉड ने बताया था कि पीरियड्स के दौरान कई औरतों को उतनी ही तकलीफ होती है जितनी एक हार्ट अटैक के दौरान होती है।

डिस्मेनोरिया पर 2012 में किए गए शोध के अनुसार कम से कम 20 फीसदी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान इतनी तकलीफ होती है कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। एक अध्ययन के अनुसार हर साल महिलाओं के पीरियड्स दर्द की वजह से काम के संबंध में प्रोडक्टिविटी में औसतन 33 फीसदी की कमी पाई गई, जो औसतन 9 दिन की कमी के बराबर है।

भारत की बात करें, तो बिहार पहला ऐसा राज्य है, जहां साल 2 जनवरी 1992 से महिला कर्मचारियों को 2 दिन की पीरियड्स के लिए छुट्टी दी जा रही है। इसके लिए उन्होंने 32 दिन तक हड़ताल की थी जिसके बाद उन्हें यह हक मिला। इसकी शुरूआत लालू प्रसाद यादव की सरकार ने की थी। इसके बाद 2017 में मुंबई में स्थित कल्चर मशीन ने 1 दिन की छुट्टी देने की शुरूआत की। साल 2020 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने पीरियड लीव देने का ऐलान किया। इस समय भारत में 12 कंपनी पीरियड लीव दे रही हैं जिसमें बायजू, स्विगी, मातृभूमि, बैजू, वेट एंड ड्राई, मैगज्टर जैसी कंपनी शामिल हैं। हाल ही में केरल सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की छात्राओं को पीरियड लीव देने का ऐलान किया था। इससे पहले कोचीन में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीयूएसएटी) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को हर महीने पीरियड लीव दिए जाने की घोषणा की थी।

गौरतलब है कि देश में पहली बार मासिक धर्म से जुड़ा मेन्स्ट्रुएशन बेनिफिट बिल, 2017 अरुणाचल प्रदेश से सांसद निनॉन्ग एरिंग ने रखा था। इस प्राइवेट बिल में कहा गया था कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाली महिलाओं को दो दिन के लिए 'पेड पीरियड लीव' यानी पीरियड्स के दौरान दो दिन के लिए छुट्टी दी जानी चाहिए। हालांकि ये बिल विरोध के चलते आगे नहीं बढ़ सका। इस संबंध में बीते साल लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने था कहा था कि 'सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल 1972' में पीरियड लीव का कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा था कि इस तरह की छुट्टियों को इन नियमों में शामिल करने का भी फिलहाल कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

उपराज्यपाल के आदेशों का ना करें पालन : दिल्ली सरकार

इन्दू रावत

दिल्ली। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के सीधे आदेशों को ना मानने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि लंबे समय से सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर चल रही खींचतान के बाद यह आदेश दिया गया है।

सूत्रों ने कहा कि नया मामला सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव का है। आप नेता पहले भी कई मौकों पर एलजी पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर अधिकारियों को आदेश जारी करने का आरोप लगा चुके हैं।

केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग सचिवों को लिखा है, लेनदेन के व्यापार नियमों (टीबीआर) के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया है।

एक सूत्र ने कहा कि सचिवों को एलजी से मिले किसी भी सीधे आदेश की जानकारी प्रभारी मंत्री को देने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने दावा किया कि उपराज्यपाल टीबीआर के नियम 49 और 50 और उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करते हुए निर्वाचित सरकार को दरकिनार करते हुए विभाग सचिवों को आदेश जारी कर रहे हैं। सूत्र ने दावा किया कि एलजी के इस तरह के सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों और संविधान के उल्लंघन में आदेशों के कार्यान्वयन को सरकार गंभीरता से लेगी।

भाजपा में शामिल हुए पार्षद पवन सहरावत

हरि सिंह रावत

दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को झटका लगा है। बवाना वार्ड-30 से आप से पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में स्थित बीजेपी दफ्तर में शुक्रवार सुबह पवन सहरावत को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका स्वागत किया।

बीजेपी में शामिल होने के बाद पवन सहरावत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। पवन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ही सदन में हंगामा करने का निर्देश दिया था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब सदन में जाते हैं माथा टेकते हैं। आप की गलत नीतियों व भ्रष्टाचार से तंग आकर मैंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आप दिल्ली में अपनी तानाशाही व अराजक रवैया बढ़ा रही है। उनकी हठधर्मिता के कारण सदन में गतिरोध हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप ने पैसे लेकर एमसीडी चुनाव में टिकट दिए थे। पवन सहरावत के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी की नरेला जोन जीत की राह आसान हो गई है। नरेला जोन में आप के पास 10 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के पास 6 सदस्य हैं। अगर चार एल्डरमैन भाजपा को वोट देते हैं तो इससे भाजपा के पास सदस्यों की संख्या भी 10 हो जाएगी।

स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए UDTS ब्रह्मास्त्र आया विश्व पुस्तक मेले में

तरुण कुमार निमेष

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहे विश्व पुस्तक मेले को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. नौ दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का आगाज हो चुका है. यहां भारी संख्या में पुस्तक प्रेमी प्रगति मैदान पर पहुंचकर अपने पसंदीदा पुस्तकों का चयन कर रहे हैं .

कोरोना संकट के बाद खासतौर पर इस तरह विधिवत पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें साहित्य, विज्ञान, फिक्शन, स्टॉक मार्किट, नॉनफिक्शन, हिंदी और अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में पुस्तक उपलब्ध हैं । वही जो लोग कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए

फोटो : तरुण कुमार निमेष

वउ्ळर यांकी की (इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र) ओथर मनीष तनेजा द्वारा लिखी गई ये पुस्तक काफी कारगर है इसमें बारीकी से बताया गया है की केसे आप स्टॉक मार्किट में अपना काम समय में ज्यादा पैसे कमा सकते है। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में स्टॉल नंबर 394- 396 पर इस पुस्तक को खरीदा जा सकता है साथ ही आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुस्तक मेले में लकी इस दुकान में इस कदर भीड़ लगी है कि लोग रुक रुक कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कम समय में कैसे पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है। वही छोटे छोटे क्विश के मध्यम से UDTS के बारे में बताया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए और मनीष तनेजा ने बताया कि जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए और जो लोग अभी नए-नए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आए हैं उनके लिए यह पुस्तक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी पहली बार विश्व में कोई ऐसी पुस्तक बनी है जिसको पढ़ कर हम कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छे स्टॉक मार्केट बना सकते हैं आइए सुनाते हैं क्या कुछ करें हैं इस पुस्तक एवं स्टॉक मार्केट में करियर को बनाने के लिए।

रिधि दर्पण
27 फरवरी-05 मार्च 2022, नई दिल्ली

सभी स्थायी रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रतिबद्ध : उपराज्यपाल

रिधि दर्पण संवाददाता

दिल्ली। उपराज्यपाल, श्री वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों / स्थानीय निकायों / स्वायत्त निकायों के लिए चयनित लगभग 1200 नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह भव्य समारोह दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बताया कि लंबे समय से रिक्त स्थायी सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए किए गए प्रतिबद्ध प्रयासों के परिणाम दिखने लगे हैं। केवल शिक्षा विभाग में ही पिछले 08 महीनों में 9369 नई भर्तियां की गई हैं और कुल मिलाकर विभिन्न विभागों/ एजेंसियों में शिक्षा निदेशालय सहित 12000 से अधिक नई भर्तियां की गई हैं। श्री सक्सेना ने बताया कि यह 2017-21 के बीच पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई प्रति वर्ष औसत भर्ती से दोगुना से अधिक है, जो केवल 5880 थी। उन्होंने जल्द से जल्द सरकार में सभी स्थायी रिक्तियों को भरने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से भर्तियों की प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।

इस अवसर पर सचिव (सेवा) ने स्वागत भाषण दिया, इस दौरान मुख्य सचिव, दिल्ली, तथा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों/ स्थानीय निकायों/ स्वायत्त निकायों के प्रमुख एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए चयनित कुल 1200 सफल अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। केवल शिक्षा निदेशालय में ही 600 नई भर्तियां की गयी हैं, जबकि दिल्ली परिवहन निगम में 360 नई नियुक्तियां की गई हैं। चयनित उम्मीदवारों की बड़ी संख्या महिला, दिव्यांग और अन्य आरक्षित श्रेणियों से है।

उपराज्यपाल ने नवनियुक्त सरकारी सेवकों को उनके ईमानदार प्रयास द्वारा नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सफलता के लिए बधाई दी। उन्होने कहा की नवनियुक्त सरकारी सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है की वे दिल्ली और देश के लिए सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुये भविष्य मे भी पूरी लगन, ईमानदारी और

पारदर्शिता के साथ काम करेंगे।

श्री सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में पदभार ग्रहण करने के दिन से ही विकास को गति देने के अलावा दिल्ली के नागरिकों को समयबद्ध तरीके से जनसेवा सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। वे खुद दिल्ली में मानव संसाधन बढ़ाने के लिए भर्ती की पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली के विभिन्न विभागों में 18000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की है। ये रिक्तियां शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग एवम अन्य विभागों में विभिन्न पदों से संबंधित हैं।

उपराज्यपाल ने आगे कहा कि सभी संबंधित विभागों के ईमानदार प्रयास के कारण दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से 18000 से अधिक पदों को भरना संभव हो पाया है। इसके अलावा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आने वाले दिनों में 25000 से अधिक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में है, क्योंकि यह उनकी प्राथमिकता है कि कोई स्थायी पद रिक्त नहीं रहना चाहिए या संविदात्मक या तदर्थ नियुक्तियों के माध्यम से भरा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भर्ती की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विभाग को उपयुक्त निर्देश दिए गए हैं।

श्री सक्सेना ने एक विशेष संवर्ग में सभी कर्मचारियों के लिए नौकरी के दौरान प्रगति का पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कैडर के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सभी योग्य कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिल सके। उन्होंने पेंशन मामलों के शीघ्र निवारण की आवश्यकता और पेंशन संबंधी मामलों के तत्काल निपटान के लिए पर्याप्त उपाय करने पर भी जोर दिया।

उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो न केवल उन्हें आजीविका का साधन प्रदान करेगा, बल्कि भारत को आने वाला समय में एक विकसित देश बनाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन भी उपलब्ध कराएगा।

मुख्य सचिव ने भी सभा को संबोधित किया और नए भर्ती हुए सरकारी सेवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके सरकारी सेवा में प्रवेश करने पर बधाई दी। उन्होंने कामना की कि वे आगे भी दिल्ली में नागरिक केंद्रित सेवा वितरण प्रणाली बनाने और भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में ईमानदारी से प्रयासरत रहेंगें।

मुख्य सचिव ने नए नियुक्त लोगों को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए 'कर्मयोगी' स्व- शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को एक वैश्विक शहर और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए सभी पक्षों को सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

जेपीसी की मांग से पीछे नहीं हटेंगे: कांग्रेस

रिधि दर्पण संवाददाता

दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ₹अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग स्वीकार करिए। जेपीसी को एक समयसीमा दे दीजिए। अडानी की जांच कराइये।₹

कांग्रेस ने अडानी समूह से जुड़े मामले को ₹मित्रवादी पूंजीवाद₹ की मिसाल करार देते हुए मंगलवार को कहा कि अगर इस मामले पर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो उसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग स्वीकार करनी चाहिए।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के संदर्भ में यह टिप्पणी की। शाह ने कहा है कि अडानी समूह के मामले में छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

रमेश ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर और सेबी प्रमुख को पत्र लिखा है। उनका कहना था कि कांग्रेस जेपीसी की मांग से पीछे नहीं हटेगी।उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ₹अगर

छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं? सरकार के लोग संसद में जेपीसी का जिक्र तक नहीं करने देते।₹

रमेश ने कहा, ₹अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग स्वीकार करिए। जेपीसी को एक समयसीमा दे दीजिए। अडानी की जांच कराइये।₹उनका कहना था, ₹कहते हैं कि जांच हिंडनबर्ग की कराएंगे। जांच तो अडानी की होनी चाहिए, प्रधानमंत्री से उनके रिश्ते की जांच करिए।₹

रमेश ने कहा, ₹कांग्रेस हमेशा निजी निवेश के पक्ष में रही है। हम हमेशा उद्यमशीलता के पक्ष में हैं। यही आर्थिक तरक्की का रास्ता है।₹ उनका कहना है, ₹हम अंध निजीकरण के खिलाफ हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी उपक्रमों को बेचा जाए।₹रमेश ने कहा, ₹हम उदारीकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उदारीकरण नियम के अनुसार और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।₹

उन्होंने कहा, ₹हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री से निजी निवेश को लेकर नहीं है, सरकारी उपक्रमों को बेचने को लेकर है, मित्रवादी पूंजीवाद को लेकर है।₹उन्होंने कहा कि अडानी का मामला ₹मित्रवादी पूंजीवाद₹ की एक मिसाल है।

कांग्रेस महासचिव के अनुसार, ₹हम बजट सत्र के अगले चरण में बार-बार जेपीसी की मांग करते रहेंगे और इस पर विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं।₹उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को कांग्रेस के नेता देश के अलग-अलग शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेंगे।

ऑनलाइन गेमिंग के लिए आएगी गाइडलाइन : MEITY

रिधि दर्पण संवाददाता

दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जल्द ही सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी। ये गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स पर आधारित होगी। इस गाइडलाइन को तैयार करते समय विशेष तौर पर यूजर सेफ्टी, वेरिफिकेशन या केवाईसी और वेलिडेशन को ध्यान में रखा गया है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ऐसे गेम बनाए जाएं जो, लोग अपनी

स्किल्स से जीत सकें न की किस्मत से। वहीं ये भी देखा जाएगा कि लोगों को कोई भी गेम खेलने पर वो उसके एडिक्ट न हो जाएं। साथ ही पैसे की भी सीमा निश्चित की जाएगी। इसमें इंडस्ट्री के सेल्फ रेगुलेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

ये बातें 17वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन (आईडीएस 2023) में गेमिंग 2.0 रेगुलेशन, पॉलिसी और गवर्नेंस विषय पर आयोजित गोष्ठी में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ निदेशक राकेश महेश्वरी ने कहीं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि एक बेहतर गाइडलाइन तैयार करने के लिए नियमित तौर पर सभी स्टेकहोल्डर्स के सुझाव लिए जा रहे हैं। आने वाले समय में गेमिंग इंडस्ट्री में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं सरकार को भी इससे बड़े पैमाने पर राजस्व मिलने की संभावना है। देश में इस क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित होंगे। इस मौके पर जागरण न्यू मीडिया के चीफ रेवेन्यू ऑफीसर गौरव अरोड़ा ने कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर सके इसके लिए जरूरी है कि एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जाए। क्रेडिबिल्टी बढ़ाई जाए और पारदर्शी तरीके से काम किया जाए। इसमें आने वाली गाइडलाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बुलंदशहर - 'नकली' दवाइयों के रैकेट का भंडाफोड़

रिधि दर्पण संवाददाता

बुलंदशहर। बुलंदशहर की ड्रग इंस्पेक्टर दीपा लाल ने आज सरकारी अस्पताल के पास न्यू चौधरी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर नकली व प्रतिबंधित दवाएं जब्त की...बुलंदशहर में नकली दवाओं का कारोबार फल फूल रहा है जिससे कई लोगों की जान पर भी बन आती है विभाग समय-समय पर छापेमारी का आभियान चलाता भी रहता है लेकिन कुछ लोग चंद सिक्कों के लालच में मासूमों की जान से खिलवाड़ करना बंद नहीं करते...नियम-कायदों को ताख पर रखकर चलनेवाला ऐसा ही एक मेडिकल स्टोर है

सरकारी अस्पताल के पास स्थित न्यू चौधरी मेडिकल स्टोर जिस पर आज छापेमारी में नकली व प्रतिबंधित मिली हैं...दवाओं को मौके पर जब्त कर लिया गया है...सैंपल को लैब भेजा रहा है और मुकदमा पंजिकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है...मेडिकल स्टोर के मालिक का नाम मो. असलम है जो बुलंदशहर का ही रहनेवाला है...छापेमारी के वक्त असलम ने अपनी ऊंची पहचान का रौब जमाया और कई डॉक्टर्स और अधिकारियों फोन मिलाए लेकिन दीपा लाल ने सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिए हैं ।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभायेगा - इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी

हरि सिंह रावत

नई दिल्ली। भारत का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा को बड़ावा देने की पहल वर्ष 2022 से की गई है, यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करने का कार्यक्रम गत पिछले वर्ष आरंभ किया है।

इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी एवमं दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पैरामेडिकल काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा को बड़ावा देने का कार्य कर रही है। यूनिवर्सिटी को नेशनल इंपोर्टेंस , अंडर पार्लियामेंट एक्ट 371 गोहाटी, आसाम भारत सरकार, अधिकृत सेल्फ आटोनोमस वर्किंग हॉनरी प्रोफेशनल डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882/1908 लागू है जिसके समक्ष यूनिवर्सिटी अपना कार्य कर रही हैं।

यूनिवर्सिटी चाउंसलर (आई एस जी डी) ने बताया कि यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के अनुभवी एवं तजुबेर्कार वर्किंग प्रोफेशनल कर्मचारी एवं उद्योगपतियों के लिए मानक उपाधि प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्य कुशलता कार्यक्रम से संबंधित और प्रभावित होकर योग्य व्यक्तियों को मानद उपाधि दी जाती है। उन्होंने कहा कि हमे खुशी है कि आज हम विभिन्न वर्गो में कार्य कर रहे शिक्षाविद, सामाजिक कार्य, मौलिक अधिकारों, शिक्षा की अलख जगाने, में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं उनको मानद उपाधि से विभूषित कर रहे हैं।, यूनिवर्सिटी चांसलर ने कहा कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है।

फोटो : इन्दू रावत

उन्होंने बताया कि हमारी मातृभूमि, भारत की दूरस्थ एवं उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, जहा डॉक्टरेट जैसे प्रोग्राम को अपने साथ जोड़ कर हमने उत्साहवर्धन रिजल्ट हासिल किया है,वही हमारे डॉक्टरेट प्रोग्राम की सर्वोच्चता उत्कर्षता ने हमे सफलता के शिखर पर पहूचाया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित राजमानी पटेल,सांसद राज्य सभा, ने अपने वक्तव्य में यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षाविधो, यूनिवर्सिटी के संचालकों,को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा को बड़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का नया शिक्षा अधिनियम 2022 लागू होने से शिक्षा के छेत्र में महत्वपूर्ण बंदलाव आयेगा, आज बेहतर शिक्षा के तहत देश के लाखो वर्किंग प्रोफेशनल एवं उद्योगपति उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है। उन्होंने बताया कि जो अपनी पढ़ाई किसी भी कारण वश बीच में छोड़ देता है,उन्हे आगे चल कर बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनमें काबिलियत की कमी नहीं होती ,उनकी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और पुनः समाज में एक नया मुकाम हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पैरामेडिकल काउंसिल। उन सभी उपाधि पाने वालो को भी बधाई जिन्होंने अपने परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन किया है।

सनातन संस्कृति का चिरन्तन सत्य

पवन कुमार कल्ला

ब्रज भूमि केवल तीर्थ क्षेत्रा का ही नाम नहीं है बल्कि संस्कृति की चिरन्तरता का ठोस सत्य है। हजारों सालों का इतिहास अपने अंक में समेटे ब्रज भूमि भारत की गहरी धार्मिक जड़ों का वट वृक्ष है जिसकी कई शाखाएं-प्रशाखाएं फैली हैं।

भौगोलिक दृष्टि से मानचित्रा धरातल पर ब्रज नाम का कोई क्षेत्रा नहीं है मगर सनातन मतावलम्बियों के हृदय में इसका वजूद है। श्रीकृष्ण के जन्म लेने तथा पश्चात लीलाओं के क्रमिक विकास किये जाने के कारण तत्कालीन क्षेत्रा विशेष धार्मिक आस्था से जुड़ गये। कालान्तर में अपने आस-पास के क्षेत्रों को भी वे सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करते रहे, फलस्वरूप कृष्ण भक्ति से जुड़े ये क्षेत्रा समय अन्तराल पर ब्रज क्षेत्रा का हिस्सा बन गये।

हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रा ब्रज का अंग माने जाते हैं। इनमें गुड़गांव, एटा, भरतपुर, डीग, कामवन, मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, दाऊजी, गिरिराज पर्वत, रमनरेत्ती, बरसाना, नन्दगांव, ग्वालियर, आगरा, मेरठ आदि प्रमुख हैं।

गर्ग संहिता के वृन्दावन खण्ड के प्रथम अध्याय में यह उल्लेखित है कि दिव्य मथुरा में जहां भी श्रीकृष्ण भगवान ने जन्म लेकर लीलाएं की थी, वहां समस्त वनों में वृन्दावन उत्तम है जो बैकुण्ठ से भी पवित्रा धाम है। वराह पुराण से ब्रज की पौराणिकता सिद्ध होती है। आदि पुरूष मनु ने भी यमुना के तट को ही अपना तपस्या का स्थल चुना था। बालक ध्रुव ने मधुवन में भगवान विष्णु की आराधना की थी। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी आदि महापुरूषों ने भी ब्रज क्षेत्रा को ही अपना आराध्य क्षेत्रा मानते हुए परिक्रमाएं की।

वस्तुतः ब्रज क्षेत्रा सनातन मतावलम्बियों की अगाध आस्था का क्षेत्रा है। प्राचीन ब्रज में बारह वन, चैबीस उपवन तथा पांच पर्वतों का अस्तित्व बताया गया है। मध्यकालीन कवि सूरदास ने भी इस बात को उद्घाटित किया है कि 'चैरासी ब्रज कोस निरन्तर खेलत है वन मोहन।' पूरे वर्ष भर में देश से लाखों नर-नारी ब्रज क्षेत्रा के तीर्थों की यात्रा करते हैं।

सनातन मतावलंबी दो प्रकार से अपनी यात्रा को अंजाम देते हैं, एक प्रकार तो वह है जिसमें मोटर, रेल, बस द्वारा यात्रा की जाती है, दूसरे प्रकार से वह जिसमें आस्तिक पद यात्रा करता है। यात्रा में भी एक मत के वे श्रद्धालु होते हैं जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ब्रज क्षेत्रा के चैरासी कोस की पदयात्रा करते हैं।

अन्य मत के श्रद्धालु वे होते हैं जो एक अथवा एक से अधिक स्थानों की पैदल परिक्रमा करते हैं। हजारों श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो पूर्व में उल्लेखित दोनों प्रकार की यात्राएं न किये जाने की स्थिति में केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करते हैं जिसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। यह वही गोवर्धन पर्वत है जिसे इन्द्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्रीकृष्ण भगवान ने अपनी अंगुली पर धारण किया था।

विष्णु पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत,स्कन्ध पुराण सहित अन्यान्य धर्म ग्रंथों में ब्रज तथा ब्रज से सम्बन्धित कथा-क्रमों का उल्लेख है। ब्रज यात्रा के लिए वैष्णव मत में भक्तों से आचार संहिता की पालना की अपेक्षा रखी जाती है जिसके अन्तर्गत ब्रज क्षेत्रा में यात्रा करने वाले आस्तिकों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे धरती पर सोयें, हमेशा नहायें, वासना से दूर रहें, चरण पदों का त्याग करें अर्थात नंगे पांव यात्रा करें, प्रतिदिन पाठ-पूजा करें, तथा श्रवण करें, सात्विक व फलाहार का सेवन करें, लोभ, मोह, मद दुगुर्णों सहित मिथ्या भाषण से दूर रहे आदि छत्तीस नियम निर्धारित हैं।

श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वल्लभाचार्य जी महाराज द्वारा ब्रज की पद यात्रा की परिपाटी शुरू की गई थी। तद्न्तर उनके उत्तराधिकारियों द्वारा यात्रा को व्यवस्थित किया गया। कालान्तर में पद यात्रा के उक्त अभियानों ने परम्परा का रूप धारण कर लिया। ब्रज में पद यात्राओं का दौर वर्ष भर चलता रहता है। मान्यता है कि यात्रा में अभाव ग्रस्त होकर रहने पर संन्यास आश्रम का फल मिलता है अगर आस्तिक हाथ में बांस की लाठी लेकर चलता है तो उसे वानप्रस्थ आश्रम का फल मिलता है।

बरसाने की लट्ठमार होली, दाऊजी का हुरंगा, फाल्गुन में पण्डे का जलती हुई होली में प्रवेश, दीपावली के अवसर पर गोवर्धन मानसी गंगा पर दीपदान, अन्नकूट दर्शन, विश्राम घाट मथुरा पर यम-द्वितीया के अवसर पर भाई-बहनों का एक साथ स्नान करना, फाल्गुन मास में ब्रज की सप्तरंगी होली, वृंदावन में रंगजी मन्दिर का रथ यात्रा मेला, बसंती कमरे के दर्शन, सावन-भादों के झूले, हिंडोलों के दर्शन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह आदि सहित अन्यान्य पर्व,उत्सव बरबस श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकृष्ट करने से नहीं चूकते और यही कारण है कि नानाविध पर्वों, उत्सवों के कारण, भक्तगणों का ब्रज क्षेत्रा में वर्ष-भर आवागमन लगा रहता है।

ब्रज वह क्षेत्रा है जिसके धूलि कण मस्तक पर लगाने योग्य हैं। ब्रज क्षेत्रा में मथुरा प्रमुख केन्द्र है। मथुरा के अलावा वृंदावन, गोकुल, दाऊजी, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन पर्वत महत्त्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। उक्त स्थानों के अलावा भी अन्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं जिनका किसी न किसी प्रकार से श्रीकृष्ण कथा-क्रम से जुड़ाव है।

ब्रज का मुख्य केन्द्र मथुरा देश के अन्य भागों से रेल एवम् सड़क मार्ग दोनों से सीधा जुड़ा हुआ है। मथुरा को केन्द्र मानते हुए आस्तिक ब्रज के महत्त्वपूर्ण स्थलों की सप्ताह भर में यात्रा कर सकता है। ब्रज क्षेत्रा में खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था सहित ठहरने की अपेक्षानुसार व्यवस्था है। उचित मानदेय देकर गाइड को साथ लेकर चलने पर यात्रा में और अधिक आनंद आता है।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलेज मेडिकल की शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा : अमित शाह

रिधि दर्पण संवाददाता

दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के सतना में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलेज मध्य प्रदेश में मेडिकल की शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा केन्द्रझप्रायोजित य़ोजना के तहत 60 और 40 के अनुपात में सतना और तीसरे चरण में राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होने जा रही है इसके बाद मध्य प्रदेश के एक भी बच्चे को मेडिकल शिक्षा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के लिए 300 करोड़ रूपए और दूसरे चरण के लिए 250 करोड़ रूपए, यानी सरकार कुल 550 करोड़ रूपए खर्च करने जा रही है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चिंता की, उन्होंने स्वच्छता भियान, उज्ज्वला योजना, योग, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट, आयुष्मान भारत, जन-औषधि केन्द्र, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की पहल और वेलनेस सेंटर्स का खाका तैयार किया। मोदी जी ने कोरोना के बाद स्वास्थ्य के पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को 60 हजार करोड़ रूपए से मजबूत किया। इसके अलावा मोदी जी ने देशभर में वेलनैस सेंटर भी बनाए। उन्होने कहा कि पिछले वर्ष के 94,452 करोड़ रूपए की अपेक्षा अब बजट में 2 लाख 30 हजार करोड़ रूपए की वृद्धि करना ये बताता है कि मोदी जी स्वास्थ्य को कितनी प्राथमिकता देते हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज अकेले मध्य प्रदेश में 38 मेडिकल कॉलेज हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि 2013-14 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, और, 2021-22 तक नरेन्द्र मोदी जी के शासन में इनकी संख्या बढ़कर 596 हो गई है। 2013-14 से पहले एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,300 थी, जो पिछले 8 सालों में 2021-22 तक बढ़कर लगभग 90 हजार करने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ ही पीजी सीटें 31 हजार थीं, जिन्हें बढ़ाकर 60 हजार करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा देशभर में 22 नए एम्स बन रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं। अकेले मध्य प्रदेश में 2055 एमबीबीएस सीटें हैं, जो नए मेडिकल कॉलेजों के बनने के बाद 3700 से अधिक हो जाएंगी। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल शुरू किए गए हैं केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और मोदी जी ने जनता के सामने लक्ष्य रखा है कि आजादी की शताब्दी के समय 2047 में भारत हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वप्रथम होगा।

उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर, निर्यात, बैंकिंग व्यवस्था आदि हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है।

उद्यमशीलता स्कीम पर जागरूकता के लिए आकांक्षी जिलों में किया गया शिविरों का आयोजन

रिधि दर्पण संवाददाता

दिल्ली। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, पशुपालन और डेयरी विभाग ने आकांक्षी जिलों में 4000 ग्राम स्तरीय सामान्य जन सेवा केन्द्रों से लगभग 2 लाख किसान जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने शिविरों के करेगा। किसानों के साथ परस्पर बातचीत के दौरान पशुपालन और डेयरी सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने इस बात पर बल दिया कि ये स्कीम आहार और चारा विकास सहित

शिविरों का आयोजन करके सामान्य जन सेवा केन्द्र नेटवर्क के माध्यम से उद्यमशीलता और विभाग की अन्य लाभार्थी-केन्द्रित योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला और पशुपालन तथा डेयरी सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने क्रमशः 22.02.2023 और 23.02.2023 को बैठक की अध्यक्षता की। उपस्थित लोगों को इन स्कीम के बारे में, साथ ही सीएससी के माध्यम से ही योजना पोर्टल पर कैसे आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। माध्यम से जुड़े किसानों को संबोधित किया और जानकारी दी कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीमों के रूप में अब प्रजनक कृषि उद्यमियों और चारा उद्यमियों का एक घटक है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) ग्रामीण उद्यमशीलता बनाने में मदद करेगा और मवेशी, डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, आहार और चारा क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं और पशुपालकों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करने में सहायता करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मार्ग प्रशस्त ग्रामीण पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमशीलता विकास और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान देंगी। सरकार देश में पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि अर्जित करने के लिए पोल्ट्री उत्पादकता, दूध और मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इस क्षेत्र के लिए विभाग का व्यापक विजन पशुधन की उत्पादकता में टिकाऊ और लाभदायक तरीके से वृद्धि से संबंधित है। योजनाओं के प्रभाव और सफलता को प्रस्तुतियों और वीडियो के माध्यम से समझाया गया।

● प्रथम पृष्ठ के शेष

दिल्ली में पिछले एक साल...

कहा था कि पिछले दिनों लड़की की हत्या करके उसके शरीर के कई टुकड़े करने और उन्हें दिल्ली में फेंकने की घटना सामने आई। नए साल की रात एक लड़की को टक्कर मारकर कार से घसीटा गया, जबकि पुलिस गश्त और जांच चौकियों पर कई गुना मुस्तैदी की अपेक्षा की जाती है। उपराज्यपाल ने कहा था कि कोई भी ढिलाई भयावह साबित हो सकती है, जैसा कुछ दिन पहले कंझावला की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुआ, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आज लड़कियां हर क्षेत्र में आग...

स्नातक और स्नातकोत्तर के एक लाख 57 हजार 290 विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्री प्रदान की गई, जिनमें 54.7 प्रतिशत महिला और 45.3 प्रतिशत पुरुष विद्यार्थी शामिल हैं। करीब 900 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई हैं। यह आंकड़ा विश्वविद्यालय के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है।

देश नफरत की आग भड़काई जा...

दबाई जा रही है।

उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी का उल्लेख करते हुए कहा, ₹यह मेरे लिए सम्मान की बात थी कि मैंने वर्ष 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला। 25 वर्षों में पार्टी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और निराशा भी हाथ लगी।₹

उन्होंने कहा कि यह बहुत सुखद स्थिति है कि अध्यक्ष के तौर पर उनकी पारी 'भारत जोड़ो यात्रा' के साथ पूरी हुई।

सोनिया ने कहा कि इस यात्रा ने कांग्रेस और लोगों के बीच संवाद की विरासत को समृद्ध किया है। उन्होंने यात्रा के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया।

कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन किया

उधर कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए पार्टी की कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के स्थायी सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 करने और अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन के सभी पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है।

पार्टी के 85वें महाधिवेशन में 85 छोटे-बड़े संशोधनों को मंजूरी दी गई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इन संशोधनों के बारे में जानकारी दी और फिर संशोधनों को मंजूरी दी गई।

पार्टी ने संविधान में संशोधन के माध्यम से फैसला किया है कि अब सीडब्ल्यूसी में 25 के स्थान पर 35 स्थायी सदस्य होंगे और कांग्रेस से जुड़े प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वतः इसके सदस्य होंगे।

कांग्रेस की ओर से किए गए अन्य संशोधनों के मुताबिक, अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिव, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन में सभी पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

संशोधन के मुताबिक संगठन के आरक्षित और गैर आरक्षित पदों में से 50 प्रतिशत अलग आरक्षण महिलाओं और युवाओं के लिए होगा।

प्रजातंत्र को तोड़ने की साज़िश रच...

तीखा प्रहार किया। खरगे ने कहा कि हम भाजपा को हराने के लिए समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल के लिए तैयार हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, ₹देश के प्रजातंत्र को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन करना होगा।"

खरगे ने कहा, ₹आज सत्ता में बैठे लोग जनता के अधिकारों पर हमला बोल रहे हैं, आज सबको 'सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान' का संकल्प लेना होगा।"

खरगे ने कहा कि आज देश सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एक ठोस विकल्प देने के मकसद से समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल करना चाहती है।

खरगे ने विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा, ₹हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एक ठोस विकल्प देने के मकसद से समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल करना चाहते हैं।₹

उन्होंने दावा किया कि इस महाधिवेशन को रोकने के लिए भाजपा सरकार ईडी का छापा मरवाया।

भारत में 47 ट्रिलियन डॉलर की...

डिजिटल क्षेत्र में भारत के विकास की बात करते हुए गोयल ने कहा, ₹2030 तक, भारत इस क्षेत्र में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात करेगा। स्टार्टअप इंडिया मिशन और डिजिटल इंडिया स्कीम के चलते ये संभव हो सकेगा। आज ब्रॉडबैंड देश के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच चुका है। देश में 800 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं।

गोयल ने इस मौके पर कहा कि आज हमारे देश के युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। युवाओं की अधिक पाने की निरंतर इच्छा और जो हासिल किया है उससे ज्यादा पाने की चाह ने ही देश को विकास के पथ पर और आगे बढ़ाया है। आज की युवा पीढ़ी में काफी उत्साह है। आज के युवाओं में कुछ अलग करने का जुनून है। ये ही देश का डिजिटल भविष्य तय करेगा। उन्होंने कहा कि हमें जेडईडी फैक्टर पर काम करना होगा। जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट' पॉलिसी को 'अगर हम अपना मंत्र मान लें तो कल्पना कीजिए कि हम इस देश को कैसे बदल सकते हैं। यही वह भारत है जिसे हम देखना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जहां 1.4 अरब लोग समृद्धि के फल का आनंद ले सकें। उन्होंने कहा कि ₹जिस अमृत काल में हमने अभी-अभी प्रवेश किया है, वह डिजिटल परिवर्तन का एक क्षेत्र बनने जा रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जहां ऊर्जा जगत में बदलाव होंगे - ऊर्जा स्रोतों का विशाल पुनर्वितरण होगा। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित कर दुनिया में भारत की स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। आईडीएस, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डिजिटल सम्मेलन है। यहां 500 से अधिक डिजिटल ब्रांडों के प्रतिनिधित्व और 3000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 60 से अधिक सत्रों में नीति निमार्ताओं, नियामकों, उद्योग कप्तानों और विषय के दिग्गजों सहित 150 से अधिक वक्ताओं को एक साथ लाया गया। शिखर सम्मेलन का समापन 57 श्रेणियों में प्रतिष्ठित इंडिया डिजिटल अवाड्र्स (13वें संस्करण) के विजेताओं की घोषणा के साथ हुआ।

अर्थव्यवस्था की विकास दर ऊंची रहेगी: राजीव

संवाददाता

दिल्ली। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार के सुधारों के कारण भारत ऊंची विकास दर की राह पर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था के छह प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। कुमार ने कहा कि उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था में आने वाली मंदी से भविष्य में बड़े जोखिम सामने आएंगे। उन्होंने कहा, 'सरकार ने पिछले आठ साल के दौरान जो सुधार किए हैं उनसे देश के पास ऊंची विकास दर की राह पर बने रहने का अच्छा मौका है। हम 2023-24 में छह प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने में सफल रहेंगे।' कुमार ने कहा कि अर्थव्यवस्था के नीचे की तरफ जाने को लेकर कई जोखिम हैं। विशेषरूप से अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा, 'हमें इन चुनौतियों का सामना सावधानी से तैयार नीतिगत उपायों के जरिये निर्यात के प्रयासों को समर्थन देकर करना होगा। इसके अलावा हमें घरेलू के साथ विदेशी स्त्रोतों से निजी निवेश का प्रवाह बढ़ाना होगा।' भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि 2023-24 में भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में अगले वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर के 6.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया है।

ऊंची महंगाई दर को लेकर सवाल पर कुमार ने कहा कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि महंगाई नियंत्रण में रहे। उन्होंने कहा, 'साथ ही सर्दियों की अच्छी फसल खाद्य कीमतों को कम रखने में मदद करेगी।'कल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.4 प्रतिशत रहेगी। यह संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के अनुरूप ही है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। जनवरी में भारत की रिटेल महंगाई दर 6.52 प्रतिशत रही थी।

पुरानी पेंशन की मांग पर बीच का रास्ता

संवाददाता

दिल्ली। मोदी सरकार पुरानी पेंशन की मांग पर बीच का रास्ता निकालने का प्लान कर रही है। सरकार की तरफ से पहले विकल्प के तौर पर यह विचार किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत प्राप्त अंतिम वेतन के करीब 50 प्रतिशत पर गारंटीशुदा पेंशन दी जाए। इस नियम के लागू होने से सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ डाले बिना मौजूदा एनपीएस में बदलाव किया जा सकेगा। सूत्रों का दावा है कि अधिकारियों ने ऐसे प्लान किया है कि एनपीएस में इस तरह बदलाव हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एकमुश्त राशि के रूप में 41.7 प्रतिशत राशि मिल जाए और बाकी 58.3 प्रतिशत राशि वार्षिकीकरण के आधार पर मिले। एक विश्लेषण से यह भी पता चला है कि यदि केंद्र व राज्य सरकार के योगदान (14 प्रतिशत) से निर्मित 58.3 प्रतिशत कोष का वार्षिकीकरण किया जाता है तो एनपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन का लगभग 50 प्रतिशत हो सकती है। इस पर सरकार की तरफ अभी तक किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

दरअसल पुरानी पेंशन योजना की मांग पर जंग तेज होती जा रही है। हाल ही में हरियाणा में सैकड़ों पूर्व और मौजूदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के पास पुरानी पेंशन की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने की थी। इससे पहले कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी हैं। पुरानी पेंशन को बहाल करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इसे देशभर में बहाल करने की मांग की थी।

पीएम किसान सम्मान निधि किस्त होली से पहले

संवाददाता

दिल्ली। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत देश के योग्य किसानों को सरकार की तरफ से सालाना आधार पर 6000 रुपये दिए जाते हैं हालांकि, सरकार किसानों को 6000 रुपये एक साथ नहीं बल्कि 2000-2000 रुपए की 3 समान किस्तों में देती है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12वीं किस्त तक का फायदा मिल चुका है। वहीं, अब किसानों को 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच खबर है कि होली से पहले किसानों को सरकार की तरफ से गुड न्यूज मिल सकती है। अगर खबरों की मानें तो किसानों के बैंक खाते में 13वीं किस्त के पैसे होली से पहले यानी 24 फरवरी को आ सकते हैं।

सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन 24 फरवरी 2023 को इस योजना के 4 साल पूरे हो जाएंगे। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि 24 फरवरी को सरकार किसानों को अकाउंट में 13वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। ऐसे में अगर आप पीएम किसान सम्मान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ जरूरी प्रक्रिया है उसे फटाफट निपटा लें। इससे जैसे ही सरकार की ओर से 13वीं किस्त जारी की जाएगी, वह बिना किसी रुकावट के आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपने इस प्रक्रिया को पूरा करने में चूक जाते हैं तो आपके किस्त के पैसे नहीं आएंगे। दरअसल, इस योजना के अंतर्गत 13वीं किस्त को लेकर सरकार ने काफी पहले ही यह बात साफ कर दिया है कि अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और अगली किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।

ट्राइफेड के ट्राइब्स इंडिया स्टोर उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद और भौगोलिक संकेत के साथ टैग किया गया

दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग (डीओसी) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जिला स्तर पर टिकाऊ रोजगार सृजित करना है। इसके पीछे सोच देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करने की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की अपील के अनुसरण में और भारत की वर्तमान जी20 अध्यक्षता के साथ, भारत सरकार के डीपीआईआईटी द्वारा कई पहल की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ओडीओपी कैटलॉग के लॉन्च के अवसर पर प्रत्येक संगठन से कार्यक्रम के सहयोग

से काम करने का अनुरोध किया।

इससे देश के प्रत्येक जिले से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, ओडीओपी ने नयी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 16-27 फरवरी, 2023 को ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) द्वारा आयोजित आदि महोत्सव में ट्राइब्स इंडिया स्टोर में परस्पर व्याप्त जनजातीय उत्पादों का मानचित्रण और टैग किया। वर्तमान में जारी आदि महोत्सव के दौरान मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ओडीओपी और जीआई एक्स ट्राइफेड उत्पाद लॉन्च किया गया।

इस अवसर पर डीपीआईआईटी की निदेशक श्रीमती सुप्रिया देवस्थली ने ओडीओपी और जीआई एक्स ट्राइफेड लॉन्च पर एक विशेष संबोधन दिया और देश भर से प्रदर्शित उत्पादों के विविध संग्रह की सराहना की।

● खेल

भारत में सुधरेगी खेलों की दशा

संवाददाता

दिल्ली। भारतीय खेल जगत में उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा के भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद अब लगने लगा है कि आने वाले समय में भारत में खेलों की दशा सुधरेगी। पीटी उषा स्वयं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की धावक रही है तथा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन में अभी तक गैर खिलाड़ी व पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। यह पहला अवसर है जब संघ की अध्यक्ष के रूप में एक महिला और वह भी खिलाड़ी की नियुक्ति हुई है। खिलाड़ी होने के नाते पीटी उषा को खिलाड़ियों के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं की पूरी जानकारी है। एक खिलाड़ी के रूप में उन्हें भी अपने करियर में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में पीटी उषा भारत में खेल व खिलाड़ियों की दशा सुधारने की दिशा में कई बेहतर काम कर सकती है। अध्यक्ष के रूप में उन्हें जो अवसर मिला है, उसका फायदा आने वाले कई पीढ़ियों को मिल सकता है।

भारतीय ओलंपिक संघ की पीटी उषा 15 वीं अध्यक्ष बनी है। इससे पूर्व चुने गए 14 अध्यक्षों में से कोई भी खिलाड़ी नहीं रहा है। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना के समय दोराबजी टाटा पहले अध्यक्ष बने थे। वह प्रतिष्ठित टाटा समूह से जुड़े हुए थे। उनके बाद महाराजा भूपिंदर सिंह, महाराजा यदाविंद्र सिंह, भलिंद्र सिंह, ओमप्रकाश मेहरा, बलिंदर सिंह, विद्या चरण शुक्ला, शिवांथी अदिथन, सुरेश कलमाडी, विजय कुमार मल्होत्रा, सुरेश कलमाडी, अजय सिंह चैटाला, नारायण रामचंद्रन, नरिंदर बत्रा अध्यक्ष रह चुके हैं।

भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। जिसका कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों व अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना और भारतीय दल का प्रबंधन करना है। यह भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की तरह भी कार्य करता है तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का भी चयन करता है। इस संघ के पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। भारतीय ओलंपिक समिति के सदस्यों में राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अन्य चुनिंदा खेल संगठनों के सदस्य शामिल हैं।

अपने जमाने की दिग्गज धाविका पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का पहला अध्यक्ष चुनने से भारतीय खेल प्रशासन में एक नए युग की शुरूआत हुई है। एशियाई खेलों में कई पदक जीतने वाली और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में

400 मीटर की बाधा दौड़ में चैथे स्थान पर रही 58 वर्षीय उषा को चुनाव के बाद शीर्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।

'पय्योली एक्सप्रेस' और 'उड़न परी' के नाम से मशहूर रही पीटी उषा ने 2000 में संन्यास लेने से पहले भारतीय और एशियाई एथलेटिक्स में दो दशक तक अपना दबदबा बनाये रखा था। पिलावुलकंडी थेक्केपारंबिल उषा का जन्म 27 जून 1964 में पय्योली गाँव में हुआ था। इन्हें पीटी उषा नाम से ही जाना जाता है। इनके पिता का नाम इ पी एम-पैतल एवं माता का नाम टी वी लक्ष्मी है। इनके पहले कोच ओ.एम. नम्बिअर थे।

पीटी उषा ने एथलीट के तौर पर अपने अन्तराष्ट्रीय करियर की शुरूवात 1980 में करांची में हुए 'पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट' से की थी। इस एथलीट मीट में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मैडल भारत के नाम किये थे। इसके बाद 1982 में पीटी उषा ने 'वर्ल्ड जूनियर इनविटेशन मीट' में हिस्सा लेकर 200 मीटर की रेस में गोल्ड मैडल एवं 100 मीटर की रेस में ब्रोंज मैडल जीता था। इसके एक साल बाद ही कुवैत में हुए 'एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप' में पीटी उषा ने 400 मीटर की रेस में नया रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मैडल जीता।

1984 में लॉसएंजिल्स में हुए ओलंपिक में पीटी उषा ने सेमी फाइनल के पहले राउंड की 400 मीटर बाधा दौड़ को अच्छे से समाप्त कर लिया था लेकिन इसके फाइनल में वे हार गई और उनको ब्रोंज मैडल नहीं मिल पाया था। हार के बाद भी पीटी उषा की यह उपलब्धि बहुत बड़ी थी। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई महिला एथलीट ओलंपिक के किसी फाइनल राउंड में पहुंची थी। इन्होने 55.42 सेकंड में रेस पूरी की थी। जो आज भी भारत के इवेंट में एक नेशनल रिकॉर्ड है।1985 में पीटी उषा ने इण्डोनेशिया के जकार्ता में 'एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप' में हिस्सा लेकर 5 गोल्ड और 1 ब्रोंज मैडल जीता। 1986 में सीओल में 10 वें 'एशियन गेम्स'में 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर बाधा एवं 4'400 मीटर रिले रेस में हिस्सा लेकर पीटी उषा विजयी रहीं और चारों गोल्ड मैडल भारत के नाम कर दिये। एक ही इवेंट में एक ही एथलीट द्वारा इतने मैडल जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 1989 में उन्होंने दिल्ली में आयोजित 'एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट' में 4 गोल्ड मैडल एवं 2 सिल्वर मैडल जीते। 1990 में 'बीजिंग एशियन गेम्स' में हिस्सा लिया। इस इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होने के बावजूद पी टी उषा ने 3 सिल्वर मैडल अपने नाम किये।

1991 में इन्होने वी श्रीनिवासन से शादी कर ली जिसके बाद इनका एक बेटा हुआ। 1998 में अचानक सबको चैंकाते हुए 34 साल की उम्र में पीटी उषा ने एथलेटिक्स में वापसी कर दी और जापान के फुकुओका में आयोजित 'एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट' में हिस्सा लेकर 200 मीटर एवं 400 मीटर की रेस में ब्रोंज मैडल जीता। 34 साल की उम्र में पीटी उषा ने 200 मीटर की रेस में अपनी खुद की टाइमिंग में सुधर किया और एक नया नेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2000 में पीटी उषा ने एथलेटिक्स से पूरी तरह से संन्यास ले लिया।मौजूदा समय में देश के अधिकांश खेल संघों के पदाधिकारियों पर भेदभाव के आरोप लगना आम बात हो गई है। खेल संघों मे गैर खिलाड़ियों व राजनेताओं के पदाधिकारी बनने से उनका ध्यान खेलों को बढ़ावा देने के बजाय अपने स्वार्थ साधना अधिक रहता है।

टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम

रूबीना दिलैक

टीवी और हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस रूबीना दिलैक का जन्म 26 अगस्त 1987 को शिमला में हुआ। शिमला के पब्लिक स्कूल और सेंट बेड्स कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह इंगलिश लिटरेचर में ग्रेजुएट हैं। उनके पिता एक लेखक हैं और वह कुछ पुस्तकें लिख चुके हैं। अपने शुरूआती दिनों में रूबीना ने दो स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीतीं और उसके बाद 2006 में मिस शिमला का ताज अपने नाम किया। 2008 में उन्होंने चंडीगढ में आयोजित 'मिस नार्थ इंडिया पेजेंट' जीता।

रूबीना आई ए एस बनना चाहती थीं लेकिन जब वह इसके लिए चंडीगढ के एक कोचिंग सेंटर पर इसकी तैयारी कर रही थीं, उन्होंने शौकिया तौर पर 'छोटी बहू' के लिए ऑडिशन दिया और चुन ली गईं। जीटीवी पर प्रसारित 'छोटी बहू' (2008-2010) में अविनाश सचदेव के साथ उन्होंने राधिका शास्त्री की भूमिका निभाकर पहचान हासिल की।

2012 में उन्होंने सोनी टीवी के 'सास बिना ससुराल' (2012) में सिमरन स्माइली गिल की भूमिका निभाई। 2013 में जीटीवी के 'पुनःविवाहः एक नई उम्मीद' (2013) में करण ग्रोवर के साथ दिव्या जखोटिया की भूमिका निभाई।

2013 से 2014 तक उन्होंने लाइफ ओके के पौराणिक शो 'देवों के देव महादेव' (2013-2014) में सीता और सब टीवी के 'जिनी और जूजू' (2013-2014) में जेनी की भूमिका निभाई। रूबीना दिलैक ने कलर्स टीवी के शक्तिः अस्तित्व एक एहसास की (2016-2021) में विवयन डीसेना के साथ सौम्या सिंह की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें कलर्स के गोल्डन पेटल अवाड्र्स 2017 में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व और आईटीए अवाड्र्स 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सम्मानित किया गया। इसमें वह अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ थीं। वह 20 सप्ताह तक बिग बॉस के घर में रहीं और विजेता के रूप में उभरीं।

दिल्ली के 12वीं आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर फेस्टिवल में देश की मशहूर गायिका निशी सिंह ने बिखेरा आवाज का जादू

नई दिल्ली हरि सिंह रावत! 12वीं आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर फेस्टिवल 2023 साहित्य उत्सव जशन- ए -अदब में देश की मशहूर गायिका निशी सिंह के सूफी कलाम और गजलों पर दर्शक जमकर झूम उठे !निशि सिंह ने न केवल खुद को एक लोकप्रिय गायिका के रूप में स्थापित किया है, बल्कि वह एक अच्छी चित्रकार भी हैं। आईजीएनसीए के सभागार में जब निशी सिंह ने हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो का कलाम छाप तिलक सब छीने मौसे नैना मिलायके पेश किया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा ! हाल ही के दिनों में 'मेरा दिल' और 'सोनी कुड़ी' गाने उनके बड़े हिट रहे। गायिका निशी सिंह ने कई मशहूर गजलों को जब अपनी मधुर आवाज में पेश किया तो सभागार में बैठे दर्शक मंत्रमुग्ध और झूमने लगे !हालाँकि उनकी शैली रोमांटिक और प्रेम से सराबोर फिल्मी गाने हैं, फिर भी वह राग, बंदिश, ठुमरी से लेकर खयाल तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कला को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानती हैं !

अन्नू कपूर ने अपनी फिल्म 'मैं दीनदयाल हूं' के लिए दिल्ली में आर एस एस के इंद्रेश कुमार जी से आशीर्वाद लिया

अभिनेता अन्नू कपूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता श्री इंद्रेश कुमार का जन्मदिन मनाने दिल्ली आए और अपनी बनने जा रही फिल्म 'मैं दीनदयाल हूं' के लिए उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर केक कटिंग समारोह का आयोजन भी किया गया। इसी दिन फिल्म के निर्देशक पवन नागपाल का जन्मदिन भी था। इसलिए एक साथ तीन केक काटा गया। अन्नू कपूर फिल्म 'मैं दीनदयाल हूं' में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भूमिका निभाते नजर आएंगे। हालांकि, बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता ने पर्दे पर कई प्रभावी भूमिकाएं निभाई हैं और एक अनूठे अभिनेता के रूप में खुद को साबित कर दिखाया है। 'डर', 'विक्की डोनर', 'एतराज' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले अन्नू कपूर ने अपनी प्रतिभा से हजारों अभिनेताओं को प्रेरित किया है।

अब वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह जल्द अपनी फिल्म 'मैं दीनदयाल हूं' की शूटिंग शुरू करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वर्ष 1940 के दशक में हिंदुत्व राष्ट्र की विचारधारा का प्रसार किया।

अन्नू कपूर एक ऐसे चरित्र को चित्रित करने के लिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं जिसका दर्शन उनके विचारों से मेल खाता है। उनका कहना है, 'ऐसे अवसर बहुत कम नसीब होते होते हैं जब किसी कलाकार को ऐसा मनपसंद किरदार निभाने का मौका मिलता है जिससे वह खुद को जोड़ सकें। मैं इस उम्र में ऐसी भूमिकाएं पाकर खुश हूं।'

फिल्म के निमार्ता रंजीत शर्मा कहते हैं, 'मैं इस फिल्म के लिए इंद्रेश कुमार (आरएसएस) से प्रेरित था। युवाओं को यह फिल्म पसंद आएगी और मुझे यकीन है कि लोग इस फिल्म से जुड़ेंगे।' टीजीएम फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म के निमार्ता हैं रंजीत शर्मा , को- प्रोडूसर हैं हरीश रेड्डी नगलमदको, कार्यकारी निमार्ता राजीव धमीजा और लेखक राशिद इकबाल हैं। फिल्म के निर्देशक हैं पवन के के नागपाल।

एक बच्ची का पिता होने का सुख ही अलग : रनबीर कपूर

'एनिमल' रनबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। कहा जा रहा है कि उनके द्वारा अदा किया गया यह एक बेहद चैंकाने वाला रोल होगा। हालांकि यह रोल रनबीर कपूर के कंफर्ट जोन से थोड़ा अलग है लेकिन इस निगेटिव रोल को प्ले करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रहने दी।

संदीप वांगा रेड्डी द्वारा डायरेक्ट की गई, हीरोइज्म से भरपूर, लार्जर देन लाइफ इस विजुअल ड्रामा वाली फिल्म में रनबीर सिंह के किरदार में ढेर सारे ग्रे शेड देखने को मिलेंगे। इस गैंगस्टर बेस्ड फिल्म में उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा।

23 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'एनिमल' रनबीर कपूर के लिए एक चैलेंजिंग फिल्म है। इसमें रश्मिका मंदाना रनबीर कपूर की पत्नी का किरदार निभा रही हैं जबकि अनिल कपूर, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी जैसे स्टार्स की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। इसे हिंदी सहित पांच अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। टी सिरीज प्रोडक्शन हाउस के एग्जीक्यूटिव महिपाल फिल्म के प्रोडयूसर हैं। 'एनिमल' के अलावा रनबीर कपूर, एक और फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' कर रहे हैं। इस रोमांटिक कॉमेडी में उनके अपोजिट श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। इसे लव रंजन डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में बोनी कपूर और डिंपल कपाड़िया रनबीर कपूर के पेरेंट्स के किरदारों में हैं। यह फिल्म होली के अवसर पर 08 मार्च को सिनेमाघरों में आ रही है। रनबीर कहते हैं 'एक बच्ची का पिता होने का सुख कुछ अलग होता है। हमारे लिए वह पल बहुत अलग था। जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं एक बच्ची का पिता बन गया हूं, मेरे दिमाग में सितारे झिलमिलाने लगते हैं'। एक बेटी का पिता बनने के बाद रनबीर कपूर ने बेटी की परवरिश के लिए बेहतर प्लानिंग तैयार कर रखी है। उनका कहना है कि 'निश्चित तौर पर पैरेंटिंग एक चुनौती भरा काम है। लेकिन इसमें भी हमें एक उदाहरण सेट करना होगा'। उनका कहना है कि 'मैं साल में 280 दिन काम करता हूं और आलिया मुझसे ज्यादा काम करती है लेकिन हम दोनों ने तय किया है कि बेटी की परवरिश के लिए ऐसा कुछ मैनेज करेंगे कि बड़ी होने के बाद बेटी को हमसे कोई शिकायत न रहे कि हमने उसे वक्त नहीं दिया'।

उस इंटरव्यू में रनबीर कपूर ने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बातें करते हुए कहा कि वह अपने ग्रांडफादर राज कपूर की एक्टिंग के नहीं बल्कि उनके डायरेक्शन के फैन रहे हैं। उन्हें उन जैसे फिल्म मेकर का पोता होने पर काफी ज्यादा गर्व है। पर कपूर खानदान से होने को वह किसी बोझ या दबाव के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक हरि सिंह रावत ने श्रीबालाजी प्रिंटर्स, 574/ए, गली नं.-2, विजय पार्क, मौजपुर दिल्ली-53 से मुद्रित कराकर म.न. 1968, जनता फ्लैट्स, जीटीबी इंकलेव, नार्थ ईस्ट दिल्ली-93 से प्रकाशित किया।
RNI No.- DELHIN/2015/61255, E-mail - ridhidarpan@gmail.com, Web. : ridhidarpan.com, Contact No.- 09213650119, 09540254160
समाचार पत्र से संबंधित सभी विवादों के लिए न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। पत्र में प्रकाशित सामग्री से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।